SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर महात्मा गांधी के शैक्षिक चिंतन का प्रभावः एक विश्लेषण

सरिता कुमारी, पी–एचडी., राजनीति विज्ञान विभाग
माड़वाड़ी महाविद्यालय, राँची विश्वविद्यालय, राँची, झारखंड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
सरिता कुमारी, पी–एचडी.
E-mail : saritaru77@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 13/08/2025
Revised on : 10/10/2025
Accepted on : 19/10/2025
Overall Similarity : 00% on 11/10/2025

शोध सार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय लोकाचार में निहित एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है, जो भारत को स्थायी रूप से एक समतामूलक और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में प्रत्यक्ष योगदान दें। नीति में एक ऐसे पाठ्यक्रम के विकास की भी परिकल्पना की गई है जो न केवल स्थानीय संस्कृति स्थानीय कौशल और स्वदेशी ज्ञान प्रणाली पर आधारित हो, बल्कि व्यक्ति को भारत के संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहरा सम्मान और समाज एवं राष्ट्र के प्रति व्यक्ति की भूमिका विकसित करने में सहायता करे जिसे गांधी जी ने लोकतांत्रिक मूल्य माना है। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा व्यक्ति को लोकतंत्र के सामाजिक पहलुओं पर आधारित एक सामूहिक जीवन जीने में सक्षम बनाए। उन्हें अपने सामाजिक परिवेश के साथ सर्वोत्तम तरीके से खुद को समायोजित करना सीखना चाहिए। शिक्षा युवाओं को सबसे जटिल लोकतांत्रिक समाजों में सक्रिय नागरिकों के रूप में अपने अधिकारों दायित्वों और जिम्मेदारियों को समझने में सक्षम बना सकती हैं। एनईपी 2020 शिक्षा प्रणाली में समुदाय को शामिल कर7ने और मातृभाषा को शिक्षण के माध्यम के रूप बढ़ावा देने पर केन्द्रित किया गया है। मातृभाषा शिक्षण से भारतीय संस्कृति और भाषा को बढ़ावा और संरक्षण मिलेगा और छोटे बच्चों को गैर–तुच्छ अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखने में मद्द मिलेगी। एक भारतीय भाषा का अनिवार्य शिक्षण हमारे भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की रक्षा और संर्वधन करेगा। वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मूल्य और शिक्षा के प्रति बहु–विषयक दृष्टिकोण पर जोर गांधी जी के विचारों से अत्याधिक प्रभावित है।

मुख्य शब्द

मातृभाषा शिक्षण, समतामूलक, आत्मनिर्भर, सामुदायिक सेवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वैचारिक अधिगम, लोकतांत्रिक सोच.

गांधी जी को शिक्षा सम्बन्धी विचार उनकी रचनात्मक विचार – पद्धति के अनुरूप राष्ट्र के नवयुवकों के नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान से प्रेरित हैं शिक्षा का उद्देश्य बच्चों तथा युवाओं को समाज तथा राष्ट्र का उपयुक्त नागरिक बनाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देश की संस्कृति एवं समय की आवश्यकताओं को नकारा नहीं जा सकता। गांधी जी पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को भारत के लिए उपयोगी नहीं मानते थे। उनके अनुसार पाश्चात्य शिक्षा साम्राज्यवाद, अहंमन्यता एवं शोषण की प्रवृत्ति का ही अंग है। भारत की ग्राम्यप्रधान सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा ही भारत के लिए उपयोगी हो सकती है। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा– प्रणाली में भी वैयक्तिक महत्वाकांक्षा के स्थान पर सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति को विशेष महत्व दिया गया है। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना में प्राथमिक शालाओं को स्वावलम्बी बनाया गया है। अहिंसा की धारणा पर आधारित यह योजना अहिंसक लोकतंत्रीय सामाजिक व्यवस्था का अभिन्न अंग मानी गई है। इस शिक्षा योजना में बच्चों की शिक्षा किसी उपयोगी हुनर के माध्यम से कराई जाती है, ताकि आजीविका का आदर्श शिक्षा से संयुक्त किया जा सके। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखने तथा अन्य सर्व विषयों की शिक्षा को उत्पादन की क्षमता से युक्त हुनर का अभिन्न अंग बनाने का उद्देश्य इस शिक्षा योजना में अंतर्निहित है। विद्यार्थी स्वयं श्रम से उत्पादित वस्तुओं से प्राप्त पारिश्रमिक द्वारा अपनी फीस का प्रबंध करेंगे। वे कार्य, अध्ययन एवं जीवन के मध्य उचित समन्वय स्थापित कर योग्य आदर्श नागरिक के रूप में विकसित होगे।

गांधी जी भारत से निरक्षरता के कलंक को दूर करना चाहते थे जिससे कि निरक्षरता के कारण जो लोगों के प्रति आर्थिक व सामाजिक अनाचार होता है उसकी समाप्ति हो। गांधी जी का मानना था कि भारत को विश्व गुरू की उपाधि तब तक फिर से प्राप्त नहीं होगी जब तक हम भारतीय साक्षर न हों जाऐं। उन्होंने लोगों को मत देने और चुने जाने के अधिकार की प्राप्ति के लिए भी साक्षरता की शर्त रखी थी, जिससे कि लोगों के मताधिकार का दुरूपयोग न हो सके और लोग निरक्षर विधि निमार्ताओं की मुर्खता पर हँसे नहीं। गांधी जी की यह मान्यता थी कि लोग न केवल साक्षर बने, बल्कि प्राथमिक शिक्षा स्तर तक तो सभी को शिक्षा प्राप्त हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वर्धा शिक्षा योजना बनाई गई। गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा को सात से चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क रखने का विचार दिया। वे लड़के तथा लड़कियों को सात वर्ष की प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् उनके द्वारा सीखे गऐ व्यवसायों में राज्य द्वारा इन्हें रोजगार की सुरक्षा दिलवाने अथवा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य पर क्रय करने की सुविधा उपलब्ध करवाना चाहते थे।

इस कार्ययोजना से सभी विद्यालय आत्मनिर्भर हो जाऐगे, क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा उत्पादन के माध्यम से अपनी फीस का प्रबंध किया जाएगा। इससे राज्य को एक महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। राज्य छात्रों के अभिभावकों को उनके बच्चों को विद्यालयों में भेजने के लिए विवश कर सकेगा। राज्य इन विद्यालयों के निरीक्षण, संयोजन एवं मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व वहन करेगा। राज्य इन विद्यालयों में उत्पादित वस्तुओं के विक्रय का प्रबन्ध करेगा। इस कार्य के लिए भूमि, भवन तथा उपकरणों की व्यवस्था विद्यार्थियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्राप्त धन के द्वार नहीं होगी, अपितु राज्य तथा स्थानीय निकायों को खर्चे का वहन करना होगा। युवाओं द्वारा अपना व्यवसायिक जीवन प्रारम्भ करने के पहले उन्हें एक वर्ष के लिए अपनी सेवाऐं अनिवार्य रूप से इस कार्य के लिए अर्पित करनी होगी ताकि शिक्षा पर होने वाले व्यय को कम से कम किया जा सके। उन युवाओं को देश के आर्थिक स्तर को ध्यान में रखकर उतना वेतन भी दिया जा सकेगा जितना उनके जीवन–निवार्ह पर होने वाले व्यय से अधिक न हो।

गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना में आर्थिक क्षमता तथा शैक्षिक क्षमता को समन्वित किया गया है किन्तु यदि कोई शिक्षण संस्थान आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो वह आर्थिक क्षमता विकसित करने के

उद्यम की ओर अग्रसर होगा। शिक्षा की दृष्टि से यह उचित नहीं होगा। आत्मनिर्भरता को इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। केवल शैक्षिक क्षमता को विकसित करने का ही उद्देश्य मूल होना चाहिए। गांधी जी की शिक्षा योजना के विरूद्ध यह भी कहा गया है कि विद्यालयों में उत्पादित वस्तुओं का विक्रय राज्य द्वारा किए जाने का अर्थ होगा कि उद्योगों का व्यापक स्तर पर समाजीकरण किया जाएगा लेकिन यह आलोचना सही नहीं है क्योंकि गांधी जी विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से यह कार्य करवाना चाहते है, अतः समाजीकरण हस्तशिल्प से जुड़ा रहे, न कि उसे केन्द्रीय उत्पादन से सम्बद्ध किया जाए। इस योजना से हस्त–शिल्पियों को कोई हानि नहीं होगी। इससे उनका समाज में सम्मान बढ़ेगा तथा श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित होगी। श्रम की नैतिक शक्ति को मान्यता मिलेगी ताकि सिद्धान्त तथा व्यवहार में होने वाले अन्तर को दूर किया जा सके।

गांधी जी की शिक्षा योजना का उद्देश्य

गांधी जी की शिक्षा योजना का उद्देश्य बालक के हाथ उसके मस्तिष्क तथा उसकी आत्मा का समन्वित विकास करना था। अन्य शिक्षा योजनाओं में बालक के हाथों का महत्व नहीं तथा उसकी आत्मा को भी दृष्टि से ओझल कर दिया गया। गांधी जी ने कार्य के द्वारा शिक्षण की योजना के संबंध में लिखा है कि ''मस्तिष्क की सच्ची शिक्षा के लिए शारीरिक अवयवों का समुचित उपयोग आवश्यक है।

शारीरिक शक्ति एवं कर्मन्द्रियों के बुद्धिपूर्वक उपयोग से सुन्दरतम और शीघ्रतम मानसिक विकास संभव है। गांधी जी का यह प्रयोग राजनीतिक दृष्टि से भी एक नवीन सामाजिक क्रांति का उद्‌बोधक है।

गांधी– ''मैं यह मानता हुँ कि शिक्षा की इस पद्धति में व्यक्ति का सबसे अधिक मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास हो सकता है। इसमें उद्योग भी आज की तरह यांत्रिक ढंग से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक ढंग से सिखाये जाएगें ताकि बाल प्रत्येक प्रक्रिया के मूल की जानकारी प्राप्त कर सके .....।''

गांधी जी की शिक्षा योजना में शहर और गांव के महत्व स्वस्थ एवं नैतिक सम्बन्धों की स्थापना की जाएगी ताकि सामाजिक असुरक्षा एवं वर्गों के मध्य विषाक्त सम्बन्धों को दूर करने में सफलता मिल सके। इसके द्वारा गांवों का निरन्तर होने वाला ह्रास नियंत्रित किया जा सकेगा और ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जा सकेगी जिसमें गरीब तथा अमीर का भेदभाव न रहे। प्रत्येक को समुचित पारिश्रमिक एवं स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होगा। इससे मालिक–मजदूरों के मध्य का वर्ग–संघर्ष नहीं होगा साथ ही वृहद् उद्योगों की स्थापना की जरूरत या इसकी स्थापना में लगने वाली विपुल पूँजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विदेशों से मिलने वाली मशीनों अथवा तकनीकी जानकारी पर निर्भरता भी समाप्त हो जाएगी। उच्चस्तरीय तकनीकी चातुर्य पर निर्भरता भी समाप्त हो जाने से जनसमुदाय का भविष्य स्वयं उनके हाथों में सुरक्षित रहेगा। गांधी जी हिंसा और जो–जबरदस्ती के खिलाफ थे। लेकिन भारत में व्याप्त निरक्षरता को दूर करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने 7–14 वर्ष तक की शिक्षा को अनिवार्य बनाने की बात कही। प्राथमिक शिक्षा का खर्च राज्य वहन करेगा, क्योंकि इससे लोगों का एक न्युनतम शिक्षा स्तर बनेगा, जो समाज और राज्य दोनों की गुणवता को बढ़ाएगा इसलिए सामान्य करों के द्वारा एकत्रित राज्य कोष से प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करना वाजिब होगा।

गांधी जी ने विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा में भी क्रांतिकारी परिवर्तन का सुझाव प्रस्तुत किया है। गांधी जी – ''मैं उच्च शिक्षा का दुश्मन नहीं हुँ। मेरी योजना में तो अधिक से अधिक और सुन्दर से सुन्दर पुस्तकालय, प्रयोगशालाऐं और शोध संस्थान रहेगें। उनसे जो ज्ञान मिलेगा, वह जनता की सम्पति होगी और जनता को उसका लाभ मिलेगा। वे निजी क्षेत्र को उच्च शिक्षा का भार सौंपना चाहते थे। उन्होंने प्राविधिक, व्यावसायिक एवं वाणिज्य संबंधी महाविद्यालयों को व्यापारी एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा चलाए जाने का उत्तरदायित्व सुझाया। कला, कृषि एवं आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों को आत्मनिर्भर रखने अथवा स्वैच्छिक चंदे से चलाए जाने का सुझाव दिया। वे राजकीय विश्वविद्यालयों को केवल परीक्षा लेने तक ही सीमित रखना चाहते है, और उन्हें परीक्षा शुल्क द्वारा आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे।

गांधी जी के विचार में उच्च शिक्षा हर सुयोग्य विद्यार्थी को मुफ्त मिलेगी लेकिन उच्च शिक्षा का सारा आर्थिक बोझ राज्य पर नहीं होगा, क्योंकि उच्च शिक्षा प्राप्त विशेषज्ञों के शिक्षण–प्रशिक्षण का लाभ केवल राज्य ही नहीं उठाता, बल्कि निजी लाभ संगठन व संस्थाऐं भी लेते है इसलिए जहाँ तक उच्च शिक्षा का प्रश्न है, उसके खर्च का वहन सार्वजनिक व निजी क्षेत्र अपनी परस्पर आवश्यकता के आधार पर करेंगे। जितने विशेषज्ञों की आवश्यकता राज्य को होगी उनके शिक्षण–प्रशिक्षण का खर्च राज्य उठाएगा और जिनकी आवश्यकता निजी क्षेत्र को होगी उनका खर्च निजी क्षेत्र उठाएगा। उच्च शिक्षा के खर्च का आर्थिक भार राज्य और निजी क्षेत्र आनुपातिक साझेदारी के आधार पर उठाऐगे।

गांधी जी विभिन्न विज्ञानों की शिक्षा को मूल्यवान मानते थे, किन्तु वे नहीं चाहते थे कि विद्यार्थी रसायनशास्त्र या भौतिकशास्त्र में ही उलझे रहे। अपनी मानसिक योग्यता के अनुसार पहले वे उपकरणों का प्रयोग सीखेंगे, बाद में लेखन का कार्य। आँखें पहले अक्षरों के चित्र पढ़ेंगी तथा जीवन का ज्ञान प्राप्त करेंगी, कान वस्तुओं तथा व्यक्तियों का नाम तथा उनके अर्थ का बोध करेगें। समस्त प्रशिक्षण प्राकृतिक तथा प्रतिक्रियात्मक होगा और त्वरित तथा सस्ता भी होगा। इस प्रकार गांधी जी की शिक्षा योजना में व्यक्ति की शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक सभी गुणों की अभिव्यक्ति समाविष्ट है। गांधी जी पाठशालाओं में नैतिक शिक्षण के पक्ष में थे। उनके अनुसार सभी धर्मों की आधारभूत नैतिकता में कोई अन्तर नहीं है।

चरित्र–निर्माण, साहस, सदगुण तथा महान आदर्शों की प्रप्ति के लिए व्यक्ति का नैतिक शिक्षण परमावश्यक हैं वे कला तथा संगीत के साथ–साथ शारीरिक प्रशिक्षण को भी महत्वपूर्ण मानते थे। उनके विचारों में सत्य और करूणा के माध्यम से व्यक्ति–समाज तथा मानवता की सच्ची सेवा कर सकता है। गांधी जी भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के साथ–साथ आधुनिकता का भी जीवन में समावेश चाहते थे। वे रूढ़ीवादी नहीं थे। उनके आदर्शों के अनुरूप स्थापित गुजरात विद्यापीठ के सम्बन्ध में उनके विचार इसके प्रमाण है जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि – ''विद्यापीठ केवल प्राचीन संस्कृति का अंधानुकरण नहीं करेगा। इसका उद्देश्य प्राचीन परम्पराओं और नवीन अनुभूतियों का समन्वय कर एक नयी संस्कृति का निर्माण करना होगा इसलिए यह विभिन्न भारतीय संस्कृतियों का समन्वय करेगा जिन्होंने भारतीय जन–जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं उनसे प्रभावित भी हुए है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कई घटकों में महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों का दर्शन होता है। NEP 2020 में शिक्षा के लिए मूल्य और बहु–विषयक दृष्टिकोण पर जोर गांधीवादी विचार से प्रभावित है। NEP 2020 . भारतीय लोकाचार में निहित एक ऐसी शिक्षा प्रणाली पर बल देता है जो भारत को स्थायी रूप से एक समतापूर्ण और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में योगदान करे। (NoHRD, 2020 पृष्ठ–6) इसमें ऐसे पाठ्यक्रम पर बल दिया गया है जो न केवल स्थानीय संस्कृति, स्थानीय कौशल और स्वदेशी ज्ञान प्रणाली पर आधारित हो बल्कि व्यक्ति में भारत के संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी भावना रखने और समाज तथा राष्ट्र के प्रति व्यक्ति की भूमिका विकसित करने में भी सहायता करें, जिसे गांधी जी का मानना था कि शिक्षा को व्यक्ति को लोकतांत्रिक जीवन जीने में सक्षम बनाना चाहिए। उन्हें अपने सामाजिक परिवेश के साथ खुद को सर्वोत्तम तरीके से समायोजित करना सीखना चाहिए। गांधी जी भारतीय शिक्षा को बाहरी हस्तक्षेप विशेष रूप से सरकार या राज्य नौकरशाही से मुक्त करना चाहते थे। एन.ई.पी. 2020 भी शिक्षा और शिक्षक के महत्व पर ध्यान केन्द्रित करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोई अभूर्त दस्तावेज नहीं है, बल्कि महान विचारक महात्मा गांधी के विचारों से गहराई से प्रेरित है। महात्मा गांधी ने 1937 में साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन के अंक में शिक्षा प्रणाली के पुर्नगठन के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत की थी। ये विचार दक्षिण अफ्रिका में उनके प्रयोगों और साबरमती आश्रमों के अनुभवों पर आधारित थे। नई तालिम की उनकी अवधारणा, जिसे बुनियादी शिक्षा के रूप में जाना जाता है, ने भारत में कई शैक्षिक विधियों की नींव के रूप में काम किया। सामाजिक परिवर्तन लाने और शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए उकने ज्ञान, रोजगार, शिक्षण और सीखने के बीच अंतर को रेखांकित किया गया। महात्मा गांधी का मूल विचार कार्य– केन्द्रीय शिक्षा को स्थानीय रूप से उपलब्ध तकनीकों के साथ जोड़ना था। इसमें छात्रों के व्यापक

विकास पर ध्यान केन्द्रित किया–शरीर–मन और आत्मा तीनों के बीच समन्वय स्थापित करने का ठोस कार्य किया गया। महात्मा गांधी ने शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण के बीच एक संतुलन पर बल दिया और कहा कि काम न केवल सामाजिक रूप उपयोगी और उत्पादक होना चाहिए बल्कि आत्मनिर्भर भी होना चाहिए।

गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का अधिकतम प्रसार सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। किसी को भी कम से कम 14 वर्षों तक शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। महात्मागांधी एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करते थे जो व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए आवश्यक हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बुनियादी शिक्षा के साथ–साथ प्रमुख कौशल विकास जैसे खेती, बागवानी, सूत कताई, काष्ठ कला, लोहार कला, मिट्टी के काम आदि का भी अनिवार्य प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

महात्मागांधी के अनुसार शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो बोझ न बने, बल्कि सुलभ, स्वीकार्य और सर्वव्यापी हो। इसलिए जहाँ तक संभव हो शिक्षण मातृभाषा में ही होना चाहिए। जब तकनीकी या वैज्ञानिक विषयों के क्षेत्र में ऐसा संभव न हो, तो दीर्घकालिक उपाय किए जाने चाहिए ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं को भी उन्नत और समृद्ध बनाया जा सके। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की उपलब्धता जन–जन तक सुनिश्चित करने तथा स्थानीय भाषाओं के माध्यम से छात्रों तक शिक्षा पहुँचाने के लिए ठोस प्रयास किए गए है।

नई शिक्षा नीति इस बात पर जोर देती है कि जहाँ तक संभव हो, अधिकांश उच्च शिक्षा संस्थानों में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा या पाठ्यक्रम द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा ताकि शिक्षा तक पहुँच से वंचित न रहा जाए। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य केवल डिग्री प्राप्त करना या सरकारी नौकरी पाना नहीं होना चाहिए बल्कि कौशल विकास और युवाओं को सशक्त बनाना शिक्षा प्रणाली का हिस्सा होना चाहिए ताकि लोग शिक्षित बेरोजगार होने के बजाए स्वरोजगार कर सके और दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सके तथा राष्ट्र निर्माण में अपनी प्रगति में भागदारी सुनिश्चित कर सके।

पारंपरिक कौशल के साथ–साथ 21वीं सदी में वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल भी अपरिहार्य है। इसमें न केवल पारंपरिक कौशल का आधुनिकीकरण बल्कि कम्पयुटर और सूचना प्रौद्योगिकी सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों में कौशल विकास भी शामिल है। इसी को ध्यान में रखते हुए, नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा और अधिगम के क्षेत्र में गांधीवादी सोच का विस्तार किया गया है ताकि शिक्षा प्रणाली एक कुशल व्यक्ति का निर्माण करे जो न केवल शिक्षित और कुशल हो, बल्कि मानवीय व्यक्तित्व से भी युक्त हो। यह समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में परिलक्षित होगा।

नई शिक्षा नीति में प्राचीन भारतीय सनातन ज्ञान, महान संस्कृति और परंपराओं के सार को उचित स्थान दिया गया है जो महात्मा गांधी के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। नई शिक्षा नीति में मूल्यों को पुनस्थापित करने के लिए गुरू को केन्द्र में रखकर उचित परिवर्तन किए गए है ताकि शिक्षक और छात्रों के बीच व्यावसायिक संबंध होने के बजाए छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आत्मीयता के साथ एक पूर्ण शैक्षणिक संबंध हो जिससे शिक्षकों को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त होगा। नई शिक्षा नीति नए बदलावों को समाहित किए हुए शैक्षिक परिदृश्य में साकारात्मक बदलाव लाने और एक अनुकूल वातावरण निर्माण हेतु प्रतिबद्ध हैं नई शिक्षा नीति के बाद शिक्षित छात्र एक बेहतर इंसान और कुशल नागरिक बनकर गांधी जी की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। नई शिक्षा नीति स्मरण आधारित शिक्षा की प्रचलित अवधारणा को बदलने की आवश्यकता को रेखांकित करती है और शिक्षा के प्रति एक समावेशी दृष्टिकोण पर जोर देती है जो शिक्षार्थियों में तार्किक सोच और रचनात्मकता को प्रोत्साहित कर सके। इसके समग्र विकास पर बल दिया गया है। मातृभाषा शिक्षण पर बल दिया गया है क्योंकि यही स्वभाविक अभिव्यक्ति का एकमात्र तरीका है। गांधी जी के विचारों के अनुरूप व्यक्ति को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजिटल कौशल और तकनीक जैसे आधुनिक विकल्पों में समाहित है।

छात्रों को न केवल शिक्षण– अधिगम प्रक्रिया में पर्यवेक्षक और अनुकरणकर्ता होना चाहिए, बल्कि उनके अपने तर्कसंगत विचार और अपने शिक्षकों के साथ विचारशील बातचीत करने की भावना भी होनी चाहिए, जिससे कक्षा को तर्कसंगत सोच का केन्द्र बनाया जा सके। यह गांधीवादी आदर्श NEP का केन्द्र है। नई नीति एक कार्यक्रम आधारित मूल्यांकन ढाँचे में बदलाव का सुझाव देती है। नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम के संबंध में शिक्षकों को स्वायत्तता देना और पाठ्यपुस्तकों के लिए शिक्षकों की अधीनता को समाप्त करना महत्वपूर्ण है। गांधी जी का मानना था कि ''यदि पाठ्यपुस्तकों को शिक्षा के वाहन के रूप में माना जाता है तो शिक्षक के जीवित शब्दों का बहुत कम मूल्य है। एक शिक्षक जो छात्रों को सिर्फ पुस्तकों से पढ़ाता है वह अपने विद्यार्थियों को मौलिकता नहीं देता है। शिक्षकों की भविष्य के नागरिकों को गढ़ने में बहुआयामी भूमिका है। गांधी का मूल दृष्टिकोण था कि कमजोर और हाशिए के समूहों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत किया जाना चाहिए।

समानता और समावेश की अवधारणाओं अनुप्रयोग के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मानवीय मूल्यों, सामुदायिक सेवा, और बहुसांस्कृतिक क्षमता के रूप में इन क्षेत्रों पर बल देती है। गांधी जी के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शिक्षार्थी के सम्पूर्ण विकास पर केन्द्रित होती है और एक स्थायी समाज के निर्माण के लिए अहिंसा, ईमानदारी और लचीलापन जैसे मूल्यों का संचार करती हैं। हमारा मानना है कि गांधी द्वारा परिकल्पित और राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा अनुशंसित समग्र शिक्षा दृष्टि हमारे राष्ट्र के गौरवशाली भविष्य का निर्माण करेगी।

निष्कर्ष

स्पष्ट है कि मातृभाषा, स्थानीय संदर्भ और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के महत्व पर बल देकर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विविधता और विरासत को संरक्षित करना है, जो गांधी जी के विचारों के अनुरूप है। शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने और बहु विषयक शिक्षा को बढ़ावा देने पर एन.ई.पी. 2020 का जोर, शिक्षार्थियों और शिक्षकों दोनों को सशक्त बनाने के गांधीजी के दृष्टिकोण का प्रतिबिंबन है। भारतीय लोकाचार में निहित एक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देकर, एन.ई.पी. 2020 का उद्देश्य सक्रिय नागरिकता का पोषण करना और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है, जो सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में शिक्षा के गांधी जी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। हालांकि एन.ई.पी. 2020 को क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ हैं तथापि एक समावेशी, समतामूलक और मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली के निर्माण की दिशा में यह एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है जो विद्यार्थियों के बीच रचनात्मकता, लोकतांत्रिक सोच और नैतिकता का बढ़ावा देती है।

इस प्रकार एन.ई.पी. 2020 राष्ट्रीय विकास व सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप भारत की शिक्षा व्यवस्था को पुनजीर्वित करने का प्रयास है। यह भारत को शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है जिसमें सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में गांधीजी के नैतिकता, मूल्यों व सिद्धान्तों को भरपूर स्थान दिया गया है। एन.ई.पी. 2020 से शैक्षणिक पाठ्यक्रों, शैक्षणिक संस्थानों में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इसमें नैतिक मूल्यों के साथ–साथ विषय के वैचारिक अधिगम पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है।

संदर्भ सूची

1. नागर, पुरूषोतम (2018) *आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन,* हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुररू राजस्थान।
2. रामरतन; त्यागी, रूची (2019) *भारतीय राजनैतिक चिन्तन,* स्कॉलर टेक प्रेस, अहमदाबाद।
3. त्यागी, रूची (2015) *आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन एक विमर्श,* हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय– दिल्ली युनिवर्सिटीज, दिल्ली।
4. त्यागी, रूचि (2016) *भारतीय राजनीतिक चिंतन प्रमुख अवधारणाऐं एवं चिंतन,* हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली।

5. एलन, डी. (2019), *9/11 के बाद गांधीः रचनात्मक अहिंसा और स्थिरता,* ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

6. बाला, एस. (2005) शिक्षा की गांधीवादी अवधारणाए वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता, *द इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस,* 16(3) 531–548।

7. बर्क, बी. (2000) *शिक्षा पर महात्मका गांधीः शिक्षा शास्त्र और अनौपचारिक शिक्षा का विश्वकोष,* मॉडर्न रिव्यू, कोलकात्ता।

8. गांधी, एम.के. (1938) महात्मा गांधी का उद्घाटन भाषण 8 अक्टुबर, 08 अक्टुबर 2020 के अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, दिल्ली।

9. निशंक, आर.पी. (2020) गांधी के विचारों और नई शिक्षा नीति के बीच कई समानताऐ, 11 अक्टुबर 2020 को द न्यू इंडियन एक्सप्रेस।

10. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2020) *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।

11. गांधी, एम.के. (सितंबर 2025) बुनियादी शिक्षा और छात्र, एस. नारायण संपादित, महात्मा गांधी की चयनित कृतियाँ, खण्ड – पाँच (सत्य की आवाज) पृष्ठ 408–424 में, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद।

12. पांडे, पी. (2020) *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में गांधी की खोज,* 11 अक्टूबर 2020 आउटलुक।

13. दिवाकर, डी. (2019) *भारत में नई शिक्षा नीति के मसौदे में गांधी की परिकल्पना,* मेनस्ट्रीम प्रकाशन, दिल्ली।

14. त्रिपाठी, प्रवीण (2020) नई शिक्षा नीति पर गांधी के विचारों का प्रभावः एक आंकलन, टाइम्स ऑफ इंडिया 4 अक्टूबर 2020।

15. https://www.educationtimes.com एन.ई.पी. 2020 में गांधीवादी शिक्षा, तान्या सिंह 25 मई 2022, Accessed on 04/08/2025.

16. https://www.mkgandhi.org भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर एक गांधीवादी दृष्टिकोण– भास्कर कुमार काकाती 04 सितम्बर 2025, Accessed on 06/08/2025.

****